भुखमरी या कोविड–19: करोड़ों लोगों को आज एक को चुनना दुर्भाग्यपुर्ण मजबुरी

'मई दिवस' (2020) की पूर्व संध्या पर, जब कोरोना महामारी पूरे जोर पर थी, 'अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन' (ILO) ने रोंगटे खड़े करने वाले आंकड़े पेश किये – दुनिया भर में महामारी की रोकथाम के लिए किये गये लॉकडाउन के चलते असंगठित क्षेत्र के करीब 160 करोड़ कामगार और मजदूर अत्यधिक संकट में जीवन गुजार रहे हैं। आई.एल.ओ. (ILO) के अनुसार, दुनिया भर के करीब 60 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक सुरक्षा, या बचत की सुविधा नहीं है।[1] इस असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भी भागीदारी है – कहीं ज्यादा तो कहीं कम – परंतु अक्सर उन्हें पुरुषों से कम पैसे मिलते हैं।[2]

परंतु अब क्वारंटाइन (quarantine), घर–में–बंद (confinement), ठहराव, लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण कहीं कोई काम नहीं कर पा रहा है। काम नहीं, तो आमदनी नहीं। आमदनी नहीं, तो भोजन नहीं। आई.एल.ओ. (ILO) ने बताया कि वैकल्पिक कमाई के बिना इन मजदूरों और उनके परिवारों के पास जीवित रहने का कोई साधन बचा नहीं है।[3]

अगर असंगठित क्षेत्र के कामगार खुद का पेट नहीं भर पाएंगे, तो इसका असर करोड़ों अन्य लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। यह असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही हैं जो हमारी खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को चलाते हैं। वैश्विक स्तर पर, खेती में होने वाले कुल श्रम का करीब 94 प्रतिशत इन्हीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। इनका योगदान खाद्य व्यापार, खुदरा बिक्री, तैयारी, पैकेजिंग और वितरण में काफी महत्वपूर्ण है।[4]

कोरोना वायरस के संकट ने स्वास्थ्य और खाद्य व्यवस्था के ऊपर हमारी निर्भरता को उजागर किया है। इसने दिखा दिया कि इन ''आवश्यक क्षेत्रों'' में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों को सामान्य समय में भी – कितनी कम मजदूरी मिलती है, इनके लिए कोई स्वास्थ्य सेवा व शिशु देखभाल सुविधाएं नहीं हैं, कार्यक्षेत्र में सुरक्षा उपायों के प्रावधान नदारत होते हैं, और अक्सर इनकी कोई वैधानिक पहचान नहीं होती है। इसके साथ–साथ काम की स्थितियों और ज़रूरतों पर बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है – अर्थात्, इनका कोई ट्रेड यूनियन नहीं होता है। दरअसल, वैश्विक खाद्य व्यवस्था के अंदर ये स्थिति दोनों ही तरह के मजदूरों के साथ है – चाहे वे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में। दूसरी तरफ शीर्ष खाद्य कंपनियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी तुलना में इन अग्रपंक्ति के मजदूरों की दशा काफी दयनीय है। उदाहरण के लिए, नेस्ले (Nestle) ने – जो विश्व की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी है – अप्रैल 2020 में अपने शेयरधारकों को 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर (तकरीबन 61000 करोड रु.) का लाभांश प्रदान किया। ये रकम संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के वार्षिक बजट से भी कहीं ज्यादा है।[5]

---

[1] कॉन्ट्रेक्ट पर रखे गए घरेलु मजदूर, किसान या पंजीकृत विक्रेता असंगठित क्षेत्र की परिभाषा में नहीं आते हैं।

[2] ILO, "Women and men in the informal economy: A statistical picture", 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf

[3] ILO, "As job losses escalate, nearly half of global workforce at risk of losing livelihoods", 29 April 2020, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm

[4] ILO, "Women and men in the informal economy: A statistical picture", 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf, page 21.

[5] Nestlé, "Results of the 153rd Annual General Meeting of Nestlé S.A. held on April 23, 2020", https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-04/annual-general-meeting-2020-summary-minutes-en.pdf. In 2018, the WFP raised US$7.2 billion, see: https://www.wfp.org/overview

अब सवाल यह उठता है कि सभी लोगों के लिए भोजन कैसे सुनिश्चित किया जाए? साथ ही खेत से लेकर उपभोक्ता तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था में जुटे अग्रपंक्ति के कामगारों को कैसे सुरक्षित एवं स्वस्थ रखा जाए। दुर्भाग्यवश, पिछले दशकों में खाद्य व्यवस्था बड़ी तेजी से बदली है – अभी तक ये सवाल किसी की प्राथमिकता में नहीं था। परंतु अब ये सवाल हमारे सामने खड़े है। पर इन सवालों के जवाब उतने मुश्किल नहीं है, जितने वे दिखते हैं।

लॉकडाउन के कारण बढ़ती भुखमरी

विश्व के अधिकांश जगहों पर मार्च 2020 से लॉकडाउन चल रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग अपने–अपने घरों में, या समुदाय में बंद हैं, और काम नहीं कर पा रहे हैं। कारखाने बंद हैं, निर्माण कार्यों पर रोक लगी हई है, भोजनालय और रेस्टोरेंटों में ताला लगा है, यातायात व्यवस्था और दफ्तर, सब कुछ बंद हैं। कई देशों में, प्रवासी मजदूर और छात्र तुरंत अपने घर जाना चाहते थे, क्योंकि वहां उनके पास उनके परिवार का सहारा है। परंतु सीमाएं बंद होने और परिवहन व्यवस्था नहीं होने के कारण वे अलग–अलग जगहों पर फंसे गए।

लगता है खाद्य व्यवस्था के बारे में बिना सोचे ही कोरोना से निपटने के कदम उठाए गए हैं। इस दौरान दुनिया के अधिकांश भाग में किसान अपने खेतों में काम कर पा रहे थे, पर कृषि मजदूरों का अभाव था – खासतौर पर कटाई और रोपाई के समय। मजदूरों की कमीं के साथ–साथ किसानों के पास अपने उत्पाद और पशुओं को खेतों से कोऑपरेटिव, संग्रह केंद्र, बूचड़खाना, व्यापारियों और बाजारों तक ले जाने का कोई साधन भी नहीं था। विद्यालयों, दफ्तरों और भोजनालयों के बंद होने से पूरी व्यवस्था चरमरा गई। इससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप, दूध को बहाया जाने लगा है और पशुओं को मारने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। यहां तक की कहीं–कहीं तो किसान फसलों को मिट्टी में ही दबा रहे हैं। युगांडा जैसे देशों में मछुआरे, जो रात में मछली पकड़ा करते थे, अब कर्फ्यू के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।[6]

लॉकडाउन के बाद शहरों में हिंसा, गाली–गलौज और भ्रष्टाचार जैसे मामले इस कदर बढ़ गए कि समझ से बाहर हैं। पूर्व अफ्रीका में और एशिया के कई हिस्सों में रेहड़ी–पटरी वालों को सड़क पर पाए जाने पर चाबुक और रबर की गोलियों से मारा गया।[7] पर्याप्त खाद्य सहायता के अभाव में शहरों और उसके आसपास के इलाकों में दंगे भड़कने लगे।[8] लेबनान में ऐसे ही दंगों में एक व्यक्ति की मौत हो गई।[9] दक्षिण अफ्रीका में एक देश है – एस्वातिनी (Eswatini), जिसे पहले स्वाजीलैंड (Swaziland) के नाम से जाना जाता था। यहां की सरकार ने यह तय किया है कि वह शहरों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं कराएगी और केवल ग्रामीण इलाकों को ही ध्यान में रखा जाएगा।[10]

दूसरी तरफ, खाद्य कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान पूरी छूट दी गई है, जिससे एक तरफ तो स्वास्थ्य संकट और ज्यादा गहरा हो गया है, और दूसरी तरफ लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। कोविड–19 महामारी का सबसे गंभीर फैलाव – ब्राजील, कनाडा, स्पेन, जर्मनी और अमेरिका – के बहुराष्ट्रीय मांस प्रसंस्करण कारखानों से हुआ है। इन कारखानों में ज्यादातर मांस उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। परंतु फिर भी इन्हें 'आवश्यक सेवाओं' की सूची में रखा गया था। लॉकडाउन के दौरान भी यहां काम लगातार चलता रहा जिससे इस कारखाने के मजदूरों और आसपास के लोगों के ऊपर

---

[6] International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, "COVID-19 and the crisis in food systems", April 2020, http://www.ipes-food.org/pages/covid19

[7] Alex Esagala et al, "Canes, tears in Kampala over coronavirus", Daily Monitor, 26 March 2020, https://www.monitor.co.ug/News/National/Photos-that-will-compel-you-cancel-your-journey-Kampala/688334-5505362-g3u0ib/index.html and Boitumelo Metsing, "Food parcel protest turns ugly as cops fire rubber bullets at hungry residents", The Star, 29 Apr 2020, https://www.iol.co.za/the-star/sport/food-parcel-protest-turns-ugly-as-cops-fire-rubber-bullets-at-hungry-residents-47325962

[8] Tom Odula and Idi Ali Juma, "Stampede in Kenya as slum residents surge for food aid", Associated Press, 10 April 2020 https://komonews.com/news/nation-world/stampede-in-kenya-as-slum-residents-surge-for-food-aid

[9] Jean Shaoul, "Protester killed in Lebanon during riots against soaring food prices", World Socialist Website, 29 April 2020, https://www.wsws.org/en/articles/2020/04/29/leba-a29.html

[10] "Swaziland govt. confirms it will not feed the starving in towns and cities during coronavirus lockdown", Swazi Media Commentary, 29 April 2020, https://allafrica.com/stories/202004290702.html

संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया।[11] केवल अमेरिका भर में 6 मई 2020 तक इन मांस उत्पादन कारखानों में काम करने वाले करीब 12,000 मजदूर बीमार पड़ चुके थे। इनमें से 48 की मृत्यु भी हो चुकी है।[12] घाना जैसे देशों में समुद्री भोजन प्रसंस्करण कारखाने इस महामारी के हॉटस्पॉट है। यहां 'थाई यूनियन' (Thai Union) नामक कंपनी का एक कारखाना है जहां टूना मछली को डिब्बे (केन) में बंद किया जाता है। यहां से सबसे ज्यादा संक्रमण देशभर में फैले हैं। पूरे देश के 11 प्रतिशत कोविड–19 के मामले के पीछे ये ही जिम्मेदार है।[13] सुपर मार्केट और ई–कॉमर्स (e-commerce) प्लेटफॉर्म (जैसे वालमार्ट, अमेज़न) में काम करने वालों को भी तथाकथित 'आवश्यक सेवाओं' में रखा गया है। इन सेवाओं को चालू रखने की प्रक्रिया में खुद को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल हो रहा है। ताड़ का तेल (palm oil) के बागानों को भी काफी हद तक चालू रखा गया है ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सामान – 'साबुन' का उत्पादन किया जा सके। परंतु कई बागान स्थानीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है।[14]

इस बीमारी का इलाज तो इस महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जब से इस महामारी की शुरुआत हुई है, तब से अधिकांश असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। कमाई न होने के कारण अब वे भुखमरी की चपेट में आ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अनुसार करीब 10 देशों में यह संकट अत्यधिक गंभीर है। ये सोमालिया या दक्षिण सुडान जैसे देश हैं, जहां सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं। कोविड–19 के कारण हो रही खाद्य उपलब्धता में कमी और उसके साथ–साथ वैश्विक मंदी कई महीनों तक रहने वाली है। अब कई देश इसकी चपेट में आ रहे हैं। भारत में, 50 प्रतिशत ग्रामीण लोग लॉकडाउन के कारण अपनी खुराक से कम खा रहे हैं।[15] विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) का कहना है कि दुनिया भर में गंभीर भूखमरी की चपेट में आए लोगों की संख्या इस साल के अंत तक बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। इनकी संख्या 13.6 करोड़ से बढ़कर साल के अंत तक 26.5 करोड़ हो जाएगी।[16]

अभी से प्रभावित लोग इसका दर्द झेल रहे हैं। समाचारों के अनुसार, हायति (Haiti), अंगोला, लेबनान, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, मायोत्ते (Mayotte), भारत, और लैटिन अमेरिका में सामान्य रूप से ये सुनने को मिल रहा है – ''भुखमरी से मरने से अच्छा है कि मैं कोरोना वायरस से मरूं''।[17] बेल्जियम में कहा जा रहा है – ''या तो हम भुखमरी से मरें या करोना वायरस से, ये हम तय करेंगे।''[18] पश्चिम अफ्रीका में लोग कह रहे हैं – 'कोरोना वायरस से पहले हम भूख के शिकार हो जाएंगे'।

---

[11] United Food and Commercial Workers International Union, "UFCW calls on USDA and White House to protect meatpacking workers and America's food supply", 30 April 2020, http://www.ufcw.org/2020/04/30/covidpacking/. While European meat packers are also experiencing outbreaks, they have not been as deep and widespread as in the US where corporate concentration is higher, says IPES (op cit).

[12] Leah Douglas, "Mapping Covid-19 in meat and food processing plants", Food and Environment Reporting Network, 22 April 2020, https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-meat-and-food-processing-plants/

[13] Rachel Sapin and Drew Cherry, "Thai Union plant is source of coronavirus outbreak that sickened over 500, officials say", IntraFish, 12 May 2020, https://www.intrafish.com/processing/thai-union-plant-is-source-of-coronavirus-outbreak-that-sickened-over-500-officials-say/2-1-807547

[14] ARD, Green Advocates, JUSTICITIZ, MALOA, NMJD, RADD, Synaparcam and YVE, "We demand justice and safety for workers on Socfin's rubber/oil palm plantations during the Covid-19 pandemic", Open letter to Socfin, 29 April 2020, https://farmlandgrab.org/29602.

[15] "Coronavirus impact | Half of rural India is eating less due to COVID-19 lockdown: Survey", Monetcontrol, 13 May 2020, https://www.moneycontrol.com/news/india/covid-19-impact-half-of-rural-population-eating-less-amid-coronavirus-crisis-5259491.html

[16] Paul Anthem, "Risk of hunger pandemic as COVID-19 set to almost double acute hunger by end of 2020", WFP, 16 April 2020, https://insight.wfp.org/covid-19-will-almost-double-people-in-acute-hunger-by-end-of-2020-59df0c4a8072

[17] Bello, "Choosing between livelihoods and lives in Latin America", The Economist, 2 May 2020, https://www.economist.com/the-americas/2020/05/02/choosing-between-livelihoods-and-lives-in-latin-america; "Lebanon: A New Surge in the Popular Struggle", International Socialist League, May 4, 2020, http://lis-isl.org/en/2020/05/04/libano-un-nuevo-salto-en-la-rebelion-popular/; La Rédaction, « Ici, on a plus peur de mourir de faim que du coronavirus ! », Charlie Hebdo, 6 avril 2020, https://charliehebdo.fr/2020/04/courrier/courrier-des-lecteurs-mayotte-on-a-plus-peur-de-mourir-de-faim-que-du-coronavirus/; AFP, "Dans l'Inde confinée, les pauvres luttent pour survivre", 9 avril 2020, https://www.journaldemontreal.com/2020/04/09/dans-linde-confinee-les-pauvres-luttent-pour-survivre; AFP, "Haïti: mourir de faim aujourd'hui ou du coronavirus demain", 3 May 2020, https://www.la-croix.com/Monde/Haiti-mourir-faim-aujourd-hui-coronavirus-demain-2020-05-03-1301092306; AFP, "«Mieux vaut mourir de cette maladie que mourir de faim»: les Angolais bravent le verrouillage du virus", 6 Avril 2020, https://www.fr24news.com/fr/a/2020/04/mieux-vaut-mourir-de-cette-maladie-que-mourir-de-faim-les-angolais-bravent-le-verrouillage-du-virus.html.

[18] Annick Ovine, "'Nous, on doit choisir: mourir de faim ou crever du coronavirus'", La Libre, 16 March 2020, https://www.lalibre.be/belgique/societe/nous-on-doit-choisir-mourir-de-faim-ou-crever-du-coronavirus-5e6f91fc9978e201d8bcf20c

अब यह साफ हो गया है कि इस प्रकार से फैल रही भुखमरी अगर वैश्विक संकट के स्तर तक पहुंच गई तो इसके पीछे के कारण उत्पादन में कमी या जमाखोरी नहीं होगी। खाद्य भंडार तो पर्याप्त है, समस्या वितरण व्यवस्था में है। मौजूदा खाद्य व्यवस्था का अत्यधिक केंद्रीकृत और भूमंडलीकृत हिस्सा इस संकट को दूर कर पाने में और हमें सुरक्षित रूप से भोजन उपलब्ध करा पाने में बिलकुल नाकामयाब रहा है।

रचनात्मक सामुदायिक प्रतिक्रियाएं

कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकारों द्वारा जो प्रथम कदम उठाए गए उनमें से प्रमुख हैं – भोजनालय, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल, और ताजे सब्जियों के बाजार को बंद करना। प्रतिक्रिया के रूप में लोगों ने भोजन प्राप्त करने के अलग–अलग नवीन तरीके ढूंढ निकाले – ज्यादातर समय सोशल मीडिया की मदद से। फेसबुक और व्हाट्सएप में अलग–अलग ग्रुप बनाए गए। इनमें संयुक्त रूप से यह पता लगाया गया कि कहां–कहां खाद्य भंडार स्थित हैं। कभी–कभी सामूहिक रूप से किसानों से उत्पाद खरीदे गए। बंद पड़े रेस्टोरेंट और कैंटीन अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके खाद्य सामग्रियों (जैसे अनाज और आटा) की थोक में खरीदारी करके, उनके छोटे–छोटे पैकेट बनाकर बेचने लगे। 'उद्देश्यों का पुनर्गठन' (repurposing) अब मूल मंत्र बन गया। विभिन्न समुदाय एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से रचनात्मक और क्रियात्मक तरीकों का इस्तेमाल करके खाद्य और भोजन को ढूंढ रहे हैं और उनका वितरण कर रहे हैं।

किसान भी अपने उत्पादों को बेचने और ढोने के लिए कई नवीन तरीके अपना रहे हैं। यूरोप में उन्होंने घरों में जाकर बेचना, अस्पतालों में वितरण, और ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दिया है। इसके अलावा किसान बाजार और समुदाय–समर्थित कृषि कार्यक्रम के जरिए उपभोक्ताओं के साथ सीधा संपर्क भी किया जा रहा है।[19] एशिया में अपने वैकल्पिक बाजार को स्थापित करने के लिए किसानों ने सोशल मीडिया और ई–कॉमर्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन खरीद–फरोख्त शुरू कर दिया है।[20] उदाहरण के लिए, कर्नाटक में किसान ट्विटर (Twitter) के जरिए अपने उत्पादों का वीडियो बनाकर खरीदारों के साथ संपर्क कर रहे हैं। अन्य किसान नकद (cash) के अभाव को दूर करने के लिए और 'मांग और आपूर्ति' (supply and demand) को ध्यान में रखते हुए आपस में खाद्य सामग्रि की अदला–बादली (barter system) जैसी पुरानी पारंपरिक व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं।[21] इंडोनेशिया में इंद्रमायु (पश्चिम जावा) में मछुआरों की एक यूनियन ने एक नई शुरुआत की है जिसमें स्थानीय किसान समूहों के साथ मिलकर 'मछुआरों की खाद्य खलिहान' का गठन किया गया है जिसके तहत मछुआरे और किसान एक दूसरे से अपने उत्पादों के आदान–प्रदान बिना नकद लिए वस्तु–विनिमय के रूप में करते हैं। रेस्टोरेंट और बाजार बंद होने के कारण इन मछुआरों के पास कोई खरीदार नहीं है। वे अपनी मछलियों के बदले चावल और सब्जियां किसानों के साथ बदल लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न समुदायों को खाद्य और आजीविका सुरक्षा प्राप्त हो रही है।[22]

लैटिन अमेरिका में, ग्रामीण समुदायों के ऊपर इस वायरस का सबसे कम असर हुआ है। अधिकांश ग्रामीण समाज शहरी गरीबों को भोजन प्रदान करने के लिए संगठित हो रहा है। कोलंबिया के कौका (Cauca) प्रान्त में नासा समुदाय रहता है। इनका मानना है कि वे लम्बे समय से हर वायरस, युद्ध, और कृषि–व्यवसाय के आक्रमण से बचते आ रहे हैं, इसलिए इनका आसानी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस समुदाय ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए संयुक्त रूप से अपनी पैदावार को शहर के गरीब इलाकों में बांटने के लिए एक 'खाद्य यात्रा' (food march) का आयोजन किया।[23] ब्राजील में बिना किसी सरकारी मदद के वहां के 'भूमिहीन मजदूर आंदोलन' (Landless Workers Movement) ने करीब 600 टन पौष्टिक आहार को अस्पतालों, बेघर

---

19 European Coordination La Via Campesina, "ECVC survey on the impact of Covid-19 on peasant farming", April 2020, https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/04/ECVC-SURVEY-ON-THE-IMPACT-OF-COVID-19-ON-PEASANT-FARMING.pdf

20 Zhenzhong Si, "Commentary: How China ensured no one went hungry during coronavirus lockdown", Channel News Asia, 19 April 2020, https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-china-grocery-food-security-price-delivery-12640426

21 Shahroz Afridi, "Madhya Pradesh: Left without cash, lockdown forces villagers to adopt barter system", Free Press Journal, 22 April 2020, https://www.freepressjournal.in/bhopal/madhya-pradesh-left-without-cash-lockdown-forces-villagers-to-adopt-barter-system

22 Pandangan Jogja, "Barter Ikan Nelayan dengan Beras Petani, Cara Nelayan Bertahan di Tengah Pandemi", Kumparan, 11 Mei 2020, https://kumparan.com/pandangan-jogja/barter-ikan-nelayan-dengan-beras-petani-cara-nelayan-bertahan-di-tengah-pandemi-1tOVhGXPMQr

23 Rita Valencia, "Los nasa de Colombia dicen: Porque no seremos los mismos, hay que liberar", Ojarasca, 9 May 2020, https://ojarasca.jornada.com.mx/2020/05/09/nasa-de-colombia-porque-no-seremos-los-mismos-hay-que-liberar-1000.html

लोगों, और अन्य कमजोर समुदायों को देश के 24 अलग–अलग राज्यों में दान दिया।[24] इनके सदस्य शहरी भोजनालयों को सामुदायिक रसोई में बदल रहे हैं और शैक्षणिक संस्थानों के भवन को अस्पतालों में बदल रहे हैं, जहां स्वस्थ्यकर्मी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।[25]

जिम्बाब्वे (अफ्रीका) में, लॉकडाउन के कारण देशभर के बड़े–बड़े खेतों से कृषि उत्पाद को ढोने की व्यवस्था चरमरा गई। इसकी भरपाई के लिए छोटे किसानों ने, अपने सीमित क्षमता के साथ, मोर्चा थाम लिया। ये छोटे किसान सब्जियों और अन्य सामग्रियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए नए–नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था में बड़े किसानों के बदले छोटे किसानों के योगदान को देखकर किसान संगठनों का ये कहना है कि अभी भी जिम्बाब्वे के 15 लाख छोटे किसान पूरे देश को खिला पाने में सक्षम हैं।[26]

स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज, और निजी कंपनियां अपने–अपने हिस्से का काम कर रही हैं। वियतनाम में 'चावल ए.टी.एम.' की शुरूआत की गई है। इन ए.टी.एम. के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी शारीरिक संपर्क या जमाखोरी के रोजाना मुफ्त में चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।[27] भारत के केरल में एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम 'शुभिक्षा केरलम' है। इसका मकसद सब्सिडी, ढांचागत विकास और अन्य सहयोगी उपायों द्वारा खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना।[28] थाईलैंड में बैंकॉक के स्थानीय अधिकारियों की मदद से सब्जी की मोबाइल दुकानों की फिर से शुरुआत की गई है। शहर के छोटे उत्पादकों और व्यापारियों को वहां का थोक बाजार सैकड़ों ट्रक उपलब्ध करा रहा है, जिससे वे घर–घर जाकर सामानों का वितरण कर सकें।[29] दूसरी तरफ अफ्रीका के कई हिस्सों में, मोटरसाइकिल वितरण सेवाओं की मदद से जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है।[30]

जहां भी जरूरत हो वहां तक भोजन पहुंचाने जैसे सामुदायिक कार्य बेहद महत्वपूर्ण है – चाहे वो एकजुटता से हो या आपसी सहयोग, स्वैच्छिक काम, सहकारिता, या फिर संगठित या असंगठित तरीके से हो। इस तरह के प्रयासों को फौरी तौर पर सभी संसाधन मुहैया कराना चाहिए। हालांकि जमीनी स्तर पर ये प्रयास ही केवल समाधान नहीं है, परंतु निश्चित रूप से ये सही दिशा की ओर इशारा करते हैं।

समुदाय आधारित खाद्य व्यवस्था की ओर बदलाव

अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा दी गई चेतावनियों से बचने के लिए हम तीन प्रकार के उपायों की मांग करते हैं:

तत्काल:

1. संसाधन समुदाय पहल (resource community initiatives): आपात स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता दी जाए एवं उनका भरपूर समर्थन किया जाए। इन प्रयासों के लिए कोष, उपकरण तथा अन्य संसाधन तुरंत मुहैया कराए जाएं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऐसे पड़ोसी समूहों या देसी समुदायों को धन या अन्य सामग्रियां देना, जिन्हें पी.पी.ई. (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट), एकत्र होने के लिए जगह या

---

[24] MST, "Produzir alimentos saudáveis e plantar árvores: a Reforma Agrária Popular no combate ao Coronavírus", 29 de março de 2020, https://mst.org.br/2020/03/29/produzir-alimentos-saudaveis-e-plantar-arvores-a-reforma-agraria-popular-no-combate-ao-coronavirus/

[25] Rebecca Tarlau, "Activist farmers in Brazil feed the hungry and aid the sick as president downplays coronavirus crisis", The Conversation, 5 May 2020, https://theconversation.com/activist-farmers-in-brazil-feed-the-hungry-and-aid-the-sick-as-president-downplays-coronavirus-crisis-136914

[26] Ignatius Banda, "COVID-19: Zimbabwe's smallholder farmers step into the food supply gap", IPS, 12 May 2020, http://www.ipsnews.net/2020/05/covid-19-zimbabwes-smallholder-farmers-step-food-supply-gap/

[27] "Vietnam entrepreneur sets up free 'rice ATM' to feed the poor amid coronavirus lockdown", 16 April 2020, https://youtu.be/lWLuIO1DGAA

[28] Samuel Philip Matthew, "COVID-19 in Kerala: Staying ahead of the curve", Newsclick, 9 May 2020, https://www.newsclick.in/COVID-19-Kerala-Highest-Recovery-Rate-Pandemic

[29] Juarawee Kittisilpa, "Thai grocery trucks get new life from coronavirus shutdown", Reuters, 14 April 2020, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-thailand-grocery-t/thai-grocery-trucks-get-new-life-from-coronavirus-shutdown-idUSKCN21W0O4?il=0

[30] AFP, "African e-commerce firms get coronavirus boost", 15 May 2020, https://news.yahoo.com/african-e-commerce-firms-coronavirus-boost-033743948.html

कमरे, भोजन सामग्री ढोने के लिए परिवहन व्यवस्था, इत्यादि की जरूरत है। इसका तरीका उन क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासन को संसाधन उपलब्ध कराना भी हो सकता है जो समुदाय–आधारित संगठनों, सहकारी समितियों और किसानों के साथ मिलकर काम कर रही हों। इसका मतलब स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त करना भी हो सकता है – चाहे वह नीतिगत कदम हों या ढांचागत विकास। कई जगहों पर ये काम पहले से ही चल रहे हैं। इसके स्तर को और आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि विश्व बैंक (World Bank), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund), तथा अन्य दाता संगठन स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सरकारों को कोष उपलब्ध कराते हैं। विडम्बना इस बात की है कि इसका ज्यादातर हिस्सा बड़ी कंपनियों को चला जाता है। यह ज्यादा जरूरी है कि स्थानीय प्रशासनों को ज्यादा पैसे आवंटित किए जाएं, जिससे वे सामुदायिक प्रयासों की बेहतर मदद कर सकें।

दीर्घकालिक:

2. किसानों और मजदूरों की स्थिति सुधारना: उत्पादन या खरीद से लेकर खुदरा बाजार तक, वितरण और खाद्य सेवाओं में शामिल सभी कर्मचारियों और मजदूरों की स्थिति को तुरंत सुधारना चाहिए। इसका मतलब है – ज्यादा मजदूरी या सार्वभौमिक मूल आय (universal basic income) जो कम आय वाले श्रमिकों को बेहतर भुगतान कर सके; या उन लोगों तक पहुंचा जाए जो 'मजदूरी अर्थव्यवस्था' (wage economy) से बाहर हैं; काम को पुनः परिभाषित करने और कार्य पद्धति पर बातचीत करने के लिए उपयुक्त अवसर (जिसे कई मजदूर संघ तलाश रहे हैं); स्वास्थ्य सेवाओं, जोखिम भुगतान (hazard pay), कार्य की सुरक्षित स्थितियां एवं शिशु देखभाल सेवा (आंगनवाड़ी) का पूरा अधिकार; और शायद सबसे ज्यादा जरूरी – समाज में बेहतर प्रतिष्ठा। किसानों को भी अपने उत्पादों को बाजार में ले जाने और सही दाम प्राप्त करने के लिए सुरक्षित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना चाहिए जिनसे उनकी आजीविका चलती है। साथ ही कृषि मजदूरों को भी उचित मजदूरी (decent wage) और स्वस्थ काम की स्थितियां (healthy work conditions) मिलनी चाहिए। कोविड–19 संकट से यह स्पष्ट हो गया है कि खेती का कार्य, परिवहन व्यवस्था और खाद्य वितरण हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की तरह जो लोग खाद्य आपूर्ति व्यवस्था में लगे हुए हैं वे भी अग्रपंक्ति में हैं। वे भी बेहतर स्थान, बेहतर वेतन और अनुकूल सुविधाओं के हकदार हैं। हमारी आर्थिक और सामाजिक संरचना में बदलाव लाने का ये सही समय है।

3. सार्वजनिक खाद्य व्यवस्था का पुनःगठन: इस वक्त सार्वजनिक और सामुदायिक–नियंत्रित बाजार को नीचे से लेकर ऊपर तक फिर से खड़ा करने और मजबूत बनाने की जरूरत है। इन बाजारों को छोटे किसानों और मछुआरों के साथ जोड़ना भी जरूरी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने साबित कर दिया है कि हम वैश्विक व्यापार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि खाद्य वितरण के ऊपर जिस प्रकार कॉर्पोरेट क्षेत्र ने नियंत्रण कर रखा है उससे हमारा अस्तित्व कितना अनिश्चित हो गया है। सरकारी कोष को बड़े खाद्य कंपनियों और कृषि–व्यापार कॉरपोरेटों को देना बंद करना होगा। इसे मजदूरों और श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराना होगा। हमें खाद्य उद्योग के अंदर संकेन्द्रण (concentration) को 'विश्वास–विरोधी' (anti-trust) या 'फैक्ट्रीनुमा–खेत विरोधी कानून' (anti-factory farm legislation) जैसे उपायों का इस्तेमाल करके निपटना होगा। इसके साथ–साथ छोटे स्तर के मछुआरों, बूचड़खानों, डेयरियों, एवं थोक बाजारों के लिए प्रत्यक्ष समर्थन (direct support) की व्यवस्था करनी होगी। हमें मालूम है कि आगे और भी महामरियां फैलेंगी। अभी ही आगे बढ़ने का सही समय है, जब एक जन–उन्मुख खाद्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक चिकित्सा अनुसंधान, सार्वजनिक अस्पताल एवं जेनेरिक दवाइयां अभी भी पेटेंट कानून के शिकंजे से बाहर हैं। भोजन केवल एक लोकहित का मुद्दा नहीं है, इसका संबंध सामाजिक कल्याण से भी है। इसे स्वास्थ्य सेवा की ही तरह सुनिश्चित, संरक्षित और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इस संकट का एक सकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि हम अपने–अपने देशों में फिर से एक सार्वजनिक व्यवस्था को पुनर्निर्माण करें। दशकों से हम निजीकरण और कॉरपोरेट नियंत्रण को सहते आए हैं। पर अब जरूरी है कि खाद्य व्यवस्था को स्थानीय और सामुदायिक प्रयासों और समाधानों के ऊपर खड़ा किया जाए। खाद्य व्यवस्था से हम इन बदलावों की शरूआत कर सकते हैं।

***